International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 947-949

ग्रामीण विकास में पंचवर्शीय योजनाओं की भूमिका

डॉ. आशीश कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य ए.पी.एम. पी.जी. कॉलेज, उझानी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्शीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न योजनायें ग्रामीण विकास के समन्वित विकास के लिये प्रारम्भ की जा रही है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनायें आज भी ग्रामीण अंचलों में व्याप्त है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास के साथ–साथ बेरोजगारी एवं गरीबी की विभीशका के निवारण हेतु चलाई जा रही है। विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य यद्यपि समरूप नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विकास का उद्दे य इन विभिन्न योजनाओं के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा है। भारत सरकार ने ग्रामीण एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में अनेक ग्रामीण विकास एवं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं उनके विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को पंचवर्शीय योजनाओं में सम्मिलित करके उन्हें लागू किया है।

मूल शब्द: ग्रामीण विकास, पंचवर्शीय योजनाओं

प्रस्तावना
भारत में जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण प्रयास सरकार की ओर से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ किया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोशित किया। इसलिए संविधान के कई उपबन्ध देश के आर्थिक विकास, जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार तथा समाज के विभिन्न वर्गो के आर्थिक हितों की रक्षा से सम्बद्ध है। भारत में सन् 1951 से योजना–बद्ध आर्थिक विकास की नींव रखी गई और तब से ही ग्रामीण विकास की ओर बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने में आने लगा है इसमें भी वि ोशकर छठी पंचवर्शीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला में बाल विकास कार्यक्रम, राश्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम ि ाक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली योजना आदि क्रियान्वित की गईं।
भारत में विभिन्न पंचवर्शीय योजनाओं के अन्तर्गत बेराजगारी एवं निर्धनता निवारण हेतु कई कार्यक्रमों को सरकार ने लागू किया है। नियोजन की प्रारम्भिक अवधि में निर्धनता निवारण को लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई वि ोश कार्यक्रम नहीं चलाये गये थे और सामूदायिक विकास योजना, राश्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कृशि एवं सम्बद्ध क्षेत्र इत्यादि के विस्तार एवं विकास के माध्यम से ही निर्धनता की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है लेकिन जब इन प्रयासों का कोई सार्थक बेरोजगारी परिणाम नहीं निकला है तब चौथी पंचवर्शीय योजना में उन्मूलन हेतु जिन कार्यक्रमों को लागू किया गया उनमें लघु कृशक विकास एजेन्सी, सीमान्त किसान एवं कृशि श्रमिक एजेन्सी, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार हेतु पुरजोर योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर एक नया कार्यक्रम राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भाुरू किया। इसी प्रकार विभिन्न पंचवर्शीय योजनाओं में ग्रामीण गरीबी व बेराजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यन्वित की जाती रहीं है। जिनमें खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम 1957–58, ग्रामीण जन ाक्ति कार्यक्रम 1960–61,ग्रामीण रोजगार क्रेश कार्यक्रम 1971–72, पाइलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972–73, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977–78, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1977–78, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्राक्षिण कार्यक्रम 1979–80, राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980–81, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम 1983–84, ग्रामीण विकास की कपार्ट योजना 1986–87, जवाहर रोजगार योजना 1989, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993–94, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993–94, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 एवं रोजगार गारण्टी कानून 2006 आदि प्रमुख है।उक्त योजनाओं को विभिन्न पंचवर्शीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्न है–

पहली पंचवर्शीय योजना–1951–56
पहली पंचवर्शीय योजना के प्रारम्भ के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी अस्त–व्यस्त थी खाद्यन्न का अभाव, कच्चे माल का अभाव, देश के बंटबारे के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति, प्रबल मुद्रास्फीति, प्रतिकूल भुगतान संतुलन और परिवहन की दुर्व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण समस्याओं की पृश्ठभूमि में पहली योजना का निर्माण किया गया था। इस योजना में कृशि को प्रमुखता दी गई थी। योजना आयोग ने पहली योजना के प्रतिवेदन में इस योजना के उद्दे य का उल्लेख निम्न भाब्दों में किया था– भारतीय योजनाकरण का केन्द्रीय उद्दे य जनता के जीवन स्तर को उॅचा करना और बेहतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करना था। किन्तु पहली योजना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृश्टि से असफल रहीं।

दूसरी पंचवर्शीय योजना–1956–61
दूसरी पंचवर्शीय योजना का प्रमुख उद्दे य आर्थिक विकास विषेशकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस तरह से गति देना था

जिससे कि जन साधारण हेतु सुख समृद्धि की नींव रखी जा सके। इसके निम्न तीन प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये थे। प्रथम अधिकतम उत्पादन, द्वितीय अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तथा तृतीय आर्थिक असमानता की समाप्ति।

तीसरी पंचवर्शीय योजना–1961–1966

तीसरी पंचवर्शीय योजना में ग्रामीण अंचलों को आत्मनिर्भर विकास की दिशा में एक विश्यिाश्ट प्रगति सुनिश्चित करना था। इसके लिए पांच लक्ष्यों की सूची बनाई गई जिनमें राश्ट्रीय आय में वृद्धि करना, कृशि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना, आधारभूत उद्योगों का विकास, मानव भाक्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग एवं आर्थिक भाक्ति का विकेन्द्रीकरण करना प्रमुख था।

तीसरी पंचवर्शीय योजना के पश्चात् तीन वार्शिक योजनाओं 1966–67, 1967–68, 1968–69 को लागू किया गया, ताकि अर्थव्यवस्था में विद्यमान तात्कालिक समस्याओं पर काबू पाया जा सके और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

चौथी पंचवर्शीय योजना –1969–74

इस योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया था, इसके लिए ग्रामीण विकास हेतु निम्न कार्यक्रमों को लागू किया गया जिनमें सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की एजेंसियों, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एवं ग्रामीण रोजगार के लि क्रेश स्कीम प्रमुख है। इसी योजना में 14 वर्श तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को भी लागू किया गया।

पॉचवी पंचवर्शीय योजना–1974–79

इस योजना को एक वर्श पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था इस योजना में निर्धनता उन्मूलन का विषेश नारा दिया गया था और इसके लिए पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होना आव यक समझा गया था। यह योजना मुख्य रूप से निर्धनता निवारण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं अन्तयोदय योजना प्रमुख है। इस योजना में ग्रामीण बेकारी दूर करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी लागू किया गया था।

छठी पंचवर्शीय योजना–1980–85

इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, राश्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली योजना आदि क्रियान्वित की गई।

सांतवी पंचवर्शीय योजना–1985–90

सांतवी योजना में एक नया कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों के लिए वृहत पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था करना था। इस योजना में राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन रोजगार गारन्टी कानून दोनों का सम्मिलित कर दिया गया था। इसके लिए अतिरिक्त नेहरू रोजगार योजना, भाहरी सूक्ष्म उधम योजना आदि को लागू किया गया था। इसी योजना में निर्धनता निवारण हेतु ग्रामीण विकास एवं रोजगार के अधिकाधिक सृजन को माध्यम बनाते हुए पूरी भाक्ति एवं संकल्प के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया।

आठवीं पंचवर्शीय योजना–1992–97

इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था तेजी से चौमुखी विकास निर्धारित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति योजना, रोजगार बीमा योजना, बाल श्रम उन्मूलन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि प्रमुख थे इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जो रणनीति तैयार की गई, उसमें शिक्षा, कृशि एवं ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई।

नवमी पंचवर्शीय योजना– 1997–2002

इस योजना में प्रमुख रूप से स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई वहीं जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आ वासन योजना को मुख्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में महत्व प्रदान किया गया। इस योजना काल में ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक नये कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई। इसमें समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम और दस लाख कुँओं की योजना को भामिल कर दिया गया।

दसवीं पंचवर्शीय योजना–2002–2007

इस योजना काल में आर्थिक कल्याण को बल दिया गया है। इस योजना काल में रोजगार के लिए एक नये कार्यक्रम रोजगार गारन्टी कानून लागू किया गया जिसका उद्दे य लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।

ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना–2007–2012

इस योजना काल में तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास की ओर अधिक बल दिया गया था इसमें मुख्य रूप से कृशि वस्तुओं की कीमतों को उन्नत करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई साथ ही कृशि में सार्वजनिक निवेश को भी बढ़ाया गया ताकि सिंचाई, वाटर भौट विकास, ग्रामीण सड़कों में जुड़ाव और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण को और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए प्रेत्यक जिले में कृशि विकास केन्द्रों की भी स्थापना की गई।

बारहवीं पंचवर्शीय योजना – 2012–2017

इस योजना में आर्थिक विकास की सालाना दर 10 प्रति ात को हासिल करने का प्रमुख लक्ष्य तय किया गया है, विश्व में आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, इसी के चलते 11 पंचवर्शीय योजना में आर्थिक विकास दर की गति को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी योजना में कृशि क्षेत्र में विकास की दर को 4 प्रतिशत तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का विशेश बल ग्रामीण अवसंरचना पर है जिससे कृशि क्षेत्र की निश्चित दर को प्राप्त किया जा सके।

उक्त अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के समन्वित विकास के लिए चलाई गई किन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दिये है, इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आव यक है–

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चलाये जा रहे रोजगार सृजक योजनाओं की व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और साथ ही इस दिशा में ग्रामीणों में जागरूकता के अभाव को भी दूर करना आव यक है।

1. जो योजनाएं पंचवर्शीय योजनाओं के माध्यम से चलायी जा

रही है उनमें आपसी तालमेल का अभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना में आपसी तालमेल नहीं हो पाया। इसी कारण से निर्धारित व्यक्तियों तक योजना का लाभ नहीं पहुॅच पा रहा है।

2. किसी भी नई योजना को तैयार करने से पूर्व सम्बन्धित लोगों से सम्पर्क करके उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाना भी अत्यन्त आव यक है। इसके लिए आव यक सर्वेक्षण भी करायें जा सकते है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा जरूरतमंद लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए खादी ग्रामाद्योग क्षेत्र का विस्तार किया जाना भी अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही गॉवों में आधारभूत संसाधनों का विकास किया जाना भी बहुत आव यक है।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार अभी भी कृशि ही है और कृशि क्षेत्र में विकास और रोजगार की अपार सम्भावनाऐं है अतः कृशि विकास हेतु कृशि में आधुनिकतम तकनीकी, यंत्र उपकरण और विधियों का प्रयोग करने के साथ–साथ ग्रामीण उद्योगों का विकास सुनिश्चित करने हेतु विशेश रणनीति बनाने की आव यकता है।
5. ग्रामीण विकास के लिए रोजगार योजनाओं के साथ विकास के अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित सफलता तथा उपलब्धियॉ न हो पाने का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है अतः ग्रामीण जनसख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण की सर्वाधिक आवश्यकता है।
6. ग्रामीण विकास हेतु जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है समय–समय पर उनकी प्रभाव ीलता की जॉच और मूल्याकन करके इनकी कमियों को पताकर उन्हें दूर किया जाना आव यक है।

उपरोक्त सुझावों को यदि चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया तो नि चत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास का प्रभावी रूप दिखाई देने लगेगा और ग्रामीण भारतीय समाज ग्रामीण प्रगति के साथ–साथ दे ा को भी विकास के पथ पर अग्रसर कर सकेगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. रोजगार तकनीकी एवं विकास – ए.के. सेन
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं महिला विकास – रतन श्रीवास्तव
3. ग्रामीण रोजगार के लिए नयी पहल – कैला चन्द्र पपनै
4. जवाहर रोजगार योजना – हाामि समिति ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या और समाधान – प्रकाा दुबे ग्रामीण रोजगार सृजन – उपेन्द्र प्रसाद